SRES ॐ NFIR

SOUTHERN RAILWAY EMPLOYEES SANGH

CENTRAL OFFICE PERAMBUR - CHENNAI

वर्ष 2016 की मीठी शुभ कामनाएँ,पोंगल, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ।

7वाँ वेतन आयोग की नशीले सिफारिशों को हटाने,बिबेक देबराय की कठुर सिफारिशों को फेंकने के लिए अनंत कालीन काम रोको के लिए तैयार होंगे...

रेलवे के प्रिय भाइयों और बहनों तथा उन्नके परिवारों को एस आ ई ई एस एन एफ आ ई आर की ओर से 2016 वर्ष की शुभ कामनाएँ एवं गणतंत्र दिवस बधाइयाँ अर्पित करते हैं। छठे वेतन आयोग गठित करवाने के साथ साथ, साक्षी प्रदान कर, केन्द्र सरकार एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर होनेवाली बैठकों में भी भाग लेकर, कई हडतालों का आयोजन करके अनगिनत आदेशों को हासिल करनेवाला संघ है एस आर ई एस – एन एफ आई आर।

एस आर ई एस - एन्न एफ आई आर की सफलताओं में कुछ –

*दास कमिटी द्वारा पिछले 40 वर्षों में कर्मचारियों को छ महीने में एक बार डी ए वृद्धि।
*लार्सजेस योजना द्वारा पिछले 10 सालों में 4200 वारिसो / आश्रितो को नौकरी।
*सभी रेल कर्मचारियों को एसी श्रेणी में यात्रा करने का आदेश।
*महिलाओँ को 730 दिन की शिशु पालन छुट्टी।
*महानेता टी वी आनंदन भूतपूर्व सांसद के प्रयास के द्वारा 1954 से पेन्शन,परिवार पेन्शन लागू।
*सेवारत कनिष्ठ कर्मचारियों को जी डी सी ई,एल डी सी ई द्वारा जे ई,ए एस एम,बुकिंग लिपिक,तकनीशियन,टी सी जैसी पदों को प्राप्त करने की रास्ता खोले जाना।
*1979 में पी एल बी बोनस योजना को लागू करके सबको बोनस ।
*पिछले 30 सालों से भी ज्यादा काल के लिए 30 प्रतिशत एच आर ए को वेतन में ही प्राप्त करवाया गया।
*अंतरिम राहत एवं महंगाई भत्ते को वेतन में जोडकर पिछले 4,5 तथा छठा वेतन आयोगों के द्वरा वेतन में बढत लाया गया ।
*प्रोत्साहन,समयोपरि भत्ता, परिवार योजना भत्ता जैसी कई भत्तों को प्राप्त करवाया गया।
*1.11.2013 से सीआरसी द्वारा अपग्रेडेशन देने का आदेश,रेलवे बोर्ड द्वारा जारी करने पर भी दक्षिण रेलवे में कई संवर्गों में उसे लागू न करने की बात का खंडन करते हैं।
*7वाँ वेतन आयोग,डीए मर्जर,अंतरिम राहत,नयी पेंशन योजना रद्द करना,वारिस को नौकरी,ऐक्ट अप्रेंटीस को नौकरी,आयकर सीमा बढत,सीलिंग रहित बोनस जैसी मुख्य 55 अंश मांग को पूरी न करनेवाले केन्द्र सरकार और रेलवे बोर्ड का खंडन करते हुए एस आर ई एस – एन एफ आई आर द्वारा चलाए गए निरंतर संघर्ष द्वारा तब के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 29.3.2014 को 7वाँ वेतन आयोग घोषित किया। फिर भी 23.12.15 को नई दिल्ली में सम्मेलनों से हुई बैठकों में डॉ एम राघवय्या जी द्वारा ज़ोर दिय़े जाने के कारण रेलवे मंत्री नें वित्त मंत्री को सिफारिश पत्र भेजने का निर्णय प्रकट किया।

केन्द्र में शासन संभालनेवाले प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी, रेलवे को निजीकृत करने के लिए बिबेक देबराय कमिटी गठित करके शत प्रतिशत विदेशी सीधी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं।

रेलवे को बचाने के लिए,भारत देश की रक्षा करने के लिए, श्रमिकों को इकट्ठित करके एस आर ई एस – एन एफ आई आर लगातार कई हड्तालें करता आ रहा है। दिनांक 28.4.2015 को हमारी मुख्य मांगों को पूरी न करनेवाले केन्द्र सरकार को खंडन करते हुए संसद घेराओ आंदोलन,बिबेक देबराय कमिटी के विरोध सिफारिशों की निंदा करते हुए 25.6.2015 को देश भर का आंदोलन, 2.9.2015 को हुए जनरल स्ट्राइक को सहयोग देते हुए धरना, 19.11.2015 को देश भर का आंदोलन चलाने के परिणामस्वरूप उसी रात को 7वाँ वेतन आयोग ने केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशों को समर्पित किया ।

वेतन आयोग सिफारिश या पिशाच आयोग षडयंत्र ?

केन्द्र सरकार के सभी श्रमिकों द्वारा आशा भरी अपेक्षा के विपरीत, नवंबर 19 को समर्पित वेतन आयोग की सिफारिश अधिकांश श्रमिकों,सेवानिवृत्त पेंशनदारों को धोखा देनेवाला रहा। 7वाँ वेतन आयोग रिपोर्ट के पेज नंबर 63 पारा नंबर 4.2.9 में गत वेतन आयोग की सिफारिशों और 7वे आयोग की तुलनात्मक दृष्टि को दर्शाया गया है,जिसके अनुसार 1986 में 4वाँ वेतन आयोग 27.6 प्रतिशत, 1996 में 5वाँ वेतन आयोग 31 प्रतिशत, 2006 में 6वाँ वेतन आयोग 54प्रतिशत वेतन को बढा, 7वाँ वेतन आयोग को 14.28 प्रतिशत बढाने की ढिंढोरा अन्याय नहीं तो क्या है?

हे केन्द्र सरकार 7वाँ वेतन आयोग की सिफारिशों के निम्नलिखितानुसार संशोधित करवाएँ।

***2.57 वेतन निर्णय को बदलकर 3.7 गुना बढाना।**
***न्यूनतम मासिक वेतन रुपये 18000- को रुपये 26000- करना।**
***1.1.2016 को 1.1.2014 से प्रभावी देना।**
***रद्द किए गए 52 भत्तों को पुनः प्रदान करना।**
***रद्द किए गए त्यौहार, बाड जैसे भत्तों को रोककर पुनःप्रदान करना।**
***24प्रतिशत,16प्रतिशत,8प्रतिशत के क्रमानुसार कम किए गए एचआरए को पुनः *30प्रतिशत,20प्रतिशत और 10 प्रतिशत बनाकर देना।**
***तकनीशियन ग्रेड II को ग्रेड I में मिलाना।**
***रिस्क अलवंस को ट्रेक मेंटेनरों को दिए जानेवाले रुपये 2700 को रुपये 5000 तथा गेट कीपरों को दिए जानेवाले रुपये 1000 को 2000 करना ।**
***स्टेशन प्रबंधक, पर्यवेक्षकों को ग्रेड पे रुपये 4800 ,रुपये 5400 प्रदान करके वेतन निर्धारित करना।**
***एमएसीपी द्वारा तीन अपग्रेडेशन के स्थान पर 5 प्रदान करना।**
***वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत बढाना ।**
***महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ते ही उसे वेतन में जोडना।**
***फिक्सड मेडिकल भत्ते को रुपये 500 से रुपये 2000 बनाकर देना।**
***20 वर्ष पूर्ति हुए कर्मचारियों को अर्हता के आधार पर बाहर भेजने को रोकना।**
***पदोन्नति के लिए वेरी गुड की योग्यता निर्णय को हटाना।**
***सेवा निवृत्त होनेवालों को 50प्रतिशत पेंशन को बदलकर 67 प्रतिशत देना।**

कई प्रमुख मांगों को हासिल करने के लिए हम एक सेना के अधीन शामिल होंगे।
एकत्रित संघर्ष से सफलता प्राप्त करेंगे।

उत्पादन को बढाने की अनेक सुविधाएँ होने पर भी काम को बाहर सौंपना क्यों ?

रेलवे में सक्षम श्रमिक होने पर भी,1000 एसी लोको इंजन,800 डीसल इंजन तैयार करके उसका मरम्मत कार्य विदेशों को सौंपने का केन्द्र सरकार के निर्णय का खंडन करते हैं।

ईसीएस द्वारा बोनस वितरित करने के लिए 7.10.2015 को रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुपालनार्थ 8.10.15 को सवारी डिब्बा कारखाना में और 8.10.15 को दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में बटवारा किये जाने से रोककर, कर्मचारियों से विकल्प देकर नकद के लिए विकल्प देनेवालों को पहले और ईसीएस द्वारा विकल्प देनेवालों को उसके बाद देने की कबड्डी खेल खेलनेवाले प्राधिकृतों के कर्मों को पहचानिएं।

बाढ़ निवारण और बाढ़ अग्रिम

तमिलनाडु में बाढ़ से बाधा हुए सभी रेलवे कर्मचारियों को रुपये 20 हजार बाढ़ निवारण देने के लिए एस आर ई एस – एन एफ आई आर ने रेलवे बोर्ड पर दबाव डाला, लेकिन बाढ़ अग्रिम रुपये 7500 को 24 मासिक इंस्टाल्मेंट में या तीन मासिक इंस्टालमेंट में डिडक्ट करने के लिए दक्षिण रेलवे प्रशासन ने 3.12.15 को आदेश जारी किया। सवारी डिब्बा कारखाना में 10.12.15 को ही बटवारा हो जाने के बाद भी दक्षिण रेलवे मात्र में क्यों आज तक प्रदान किए बिना समय बीता जा रहा है। अर्बन बैंक द्वारा बाड निवारण प्रदान किए जाने के बहाने रुपये 20 हजार ऋण प्रति माह रुपये 575 के रूप में 48 माह के इंस्टालमेंट में डिडक्ट करके ब्याज मात्र के रूप में रुपये 7600 वसूल करनेवाले प्राधिकृत हरिश्चन्द्र वेषधारी को देखें।

प्रशासन द्वारा दिए जानेवाले बाढ़ अग्रिम को रोकने के कारण अर्बन बैंक में सदस्य न होने वालों को और लोन न मांगनेवालों को भी धोखा देनेवाले प्राधिकृतों की नकली सेवा देखें।

एसआरईएस एनएफआईआर की मांगों को स्वीकार करके तमिलनाडु में हुए बाढ़ के कारण 13.11.15 ,दिसंबर 2,3, और 4 तारिखों में विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने का आदेश जारी किए महा प्रबंधक जी को धन्यवाद।

घोर नुक्सान होने के कारण, 5 किलोमीटर की नज़र में देखे बिना सब को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने के लिए एसआरईएस एनएफआईआर ने ज़ोर दिया है।

बाढ़ में बाधित जनता को एस आर ई एस निवारण सेवा

चेन्नै तिरुवत्तूर में आर ई वास स्थान में, कोसप्पूर आईएनटीयूसी नगर, कतिरवेड जैसे स्थानों में तथा तिरुवटत्तै और ओट्टेरी के अनाथ बच्चों के आश्रमों में, विळुप्पुरम, कडलूर क्षेत्रों में, पोत्तनूर वर्कशाप के एसआरईएस कार्यकर्ताओं की ओर से निवारण वस्तुएं बाधित लोगों को सीधा जाकर वितरित किये गये।

अंतर मंडलीय आवेदन स्थानांतरन के लिए पंजीकृत सेवारत कर्मचारियों को तुरंत स्थानांतरन आदेश जारी करने को दक्षिण रेलवे प्रशासन से ज़ोरदार मांग प्रस्तुत करते हैं।

रुपये 7000 सीलिंग के आधार पर पीएलबी बोनस

एस आर ई एस एन एफ आई आर द्वारा ज़ोर दिए जाने के कारण 2014-15 वित्तीय वर्ष के बोनस सीलिंग रुपये 7000 को संशोधित कर 1.9.2015 को लेबर मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाने के तुरंत बाद 8.9.2015 को रेलवे मंत्री महोदय और 5.10.15 को माननीय प्रधान मंत्री को लागू करने के लिए डॉ राघवय्या जी ने पत्र लिखा था। पुराने सीलिंग के आधार पर 7.10.15 को जारी किए गए बोनस आदेश को संशोधित कर नए सीलिंग के आधार पर 1.4.15 के पूर्व दिनांक से प्रभावी देकर लागू करने के लिए एसआरईएस एनएफ आई आर द्वारा लगातार ज़ोर देने के कारण संसद में 22.12.15 को लेबर कल्याण मंत्री द्वारा पेश किए गए नए सीलिंग रुपये 7000 के लिए अर्ह बोनस संशोधन मसोदा आवाज मत द्वारा पारित किये जाने की बात को प्रसन्नता से सूचित करते हैं।

नई दिल्ली में 23.12.15 को संपन्न् बैठक में अध्यक्ष डॉ राघवय्या जी ने बोनस अरीयर्स को तुरंत बटवारा करने के लिए रेलवे मंत्री से ज़ोर दिया।

899 पृष्ठ वेतन आयोग सिफारिश - वेतन वृद्धि है या धोखा

6 वाँ वेतन आयोग द्वारा मिल रहा वेतन						7वाँ वेतन आयोग द्वारा मिलनेवाला वेतन				
ग्रेड पे	पुराना वेतन	डीए	कुल वेतन	डिडक्शन	अब मिल रहा वेतन	ग्रेड पे	डीए	डिडक्शन	मिलनेवाला वेतन	वृद्धि
1800	7000	8750	15750	1605	14145	18000	-	3300	14700	555
1900	7730	9663	17383	1770	15623	19000	-	3490	16410	787
2000	8460	10575	19035	1934	17101	21700	-	3670	18030	929
2400	9910	12388	22298	2260	20038	25500	-	4050	21450	1412
2800	11360	14200	25560	2586	22974	29200	-	4420	24780	1806
4200	13500	16875	30375	3068	27307	35400	-	6040	29630	2053
4600	17140	21425	38565	3887	34678	44900	-	6990	37910	3232
4800	18150	22688	40838	4114	36724	47600	-	7260	40340	3616
5400	20280	25350	45630	4593	41037	53100	-	7810	45290	4253

अब मिलनेवाले वेतन से 7वाँ वेतन आयोग सिफारिश में मिलनेवाले वेतन की तुल्ना करने पर न्यूनतम वृद्दि ही वेतन में होगी। यह वेतन अगले 10 वर्ष तक बने रहने के कारण 7वाँ वेतन आयोग श्रमिकों को वंछित करना स्पष्ट दिखाई देता है।

बुरी सिफारिश को हटाने के लिए देश भर 27.1.15 से काला दिवस अनुष्ठित किया गया।

ग्रूप इंश्यूरेंस योजना में 7वाँ वेतन आयोग सिफारिश में वैज्ञानिक धोखा देखिए।

माह में रुपये 30 कटौती करके सीजीआईएस ग्रूप इंश्यूरेंस रकम को 7वाँ वेतन आयोग में बढ़ाकर रुपये 1500 कर दिया है जिसका 70 प्रतिशत बचत खाते में 30 प्रतिशत इंश्युरेंस खाते में रखा जाएगा।

उदाहरण के लिए 30 साल सेवा करनेवाले कर्मचारियों को

मासिक डिडेक्शन रुपये	वार्षिक डिडेक्शन रुपये	वार्षिक बचत रुपये	30 साल की बचत रुपये	वार्षिक बीमा 30% रुपये	30 साल में बीमा रुपये	मृत्यु होने पर कर्मचारी को रुपये
1500	18000	12600	378000	5400	1,62000	15,00,000

एलआईसी अनमोल जीवन – 2

वार्षिक बीमा जमा	5 साल बीमा जमा	न्यूनतम 5 साल जमा करने पर मृत्यु पश्चात
6229	31145	24,00,000

*** एल आई सी अनमोल जीवन – 2 पालिसी को सिर्फ 5 साल पैसा जमा करने से ही मृत्यु पश्चात रुपये 24,00,000 मिलेगा ।**

***लेकिन सी जी आई एस योजना के तहत 30 साल तक जमा करने पर भी मृत्यु पश्चात कुल बचत और बीमा मिलाकर 15,00,000 मिलेगा।**

अगर हमारे सी जी आई एस का पैसा एल आई सी अनमोल जीवन – 2 पर लगाया जाए तो 30 साल बाद मृत्यु पश्चात 1,24,00,000 मिलेगा।

प्रशासन डिडक्ट करेगा ज्यादा रकम.. देगा तो बहुत कम रकम...

एलआईसी की तुल्ना में हमे मिलनेवाले रुपये 1,24,00,000-

केन्द्र सरकार कर्मचारियों को केन्द्र सरकार ही धोखा दे सकता है क्या ?

लडकर प्राप्त किए गए अधिकारों को छीननेवाले केन्द्र सरकार को खंडन करके मांगों को हासिल करने की सफलता पाने के लिए

राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति नेता डॉ एम राघवय्या के नेतृत्व में मार्च प्रथम सप्ताह में अनंत कालीन काम रोको हडताल करेंगे ... सफलता हासिल करेंगे।

डा एम राघवय्या अध्यक्ष	पी एस सूर्य प्रकाशम महा सचिव